जमीन आसमान का फर्क है इसलिए सरकार की वह नीति उचित नही है। तो क्या आप यह जो 10 परसेट यूरिया की कीमतों में वृद्धि की है, इसे वापस लेंगे?

दूसरी बात, एक ओर बड़ी एनॉमली यह है कि इन्होंने 21 फरवरी से यूरिया की कीमते बढाने का एलान किया है और पहली अप्रैल से ये कीमतें लागू होंगी।

अभी तक जो भी स्टाक स्टाकिस्ट के पास था, उन्होंने सारे का सारा रोक लिया है और किसान को कोई भी यूरिया 21 तारीख की अनाउंसमेंट के बाद पुराने प्राइस पर नही मिलेगा। तुरन्त उन्हे इन्क्रीज लागू कर देना चाहिए था। तो इस बीच में जो लाखों-करोंड़ो रुपये उस स्टाक से कम्पनियां कमाएंगी, मंत्री जी उसे वापिस लेकर क्या किसानों को पहुचाने की कोशिश करेंगे?

श्री शीश राम ओला : माननीय उपसभापति महोदया, माननीय सद्स्य ने बड़ा अहम क्वेश्यन पूछा है। वह काफी सीनियर है और मंत्री भी रहे है, वह किसान भी है। मै उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूरिया के भाव इतने सस्ते थे और जमीन का उर्वरक सतुलन इतना बिगड़ गया था कि सस्ता होने के नाते किसान यूरिया अधिक उपयोग करते थे जो उचित नही था। जमीन के सतुलन के बिगड़ने से उसकी उपजाऊ शक्ति नही रही जो खाद डालने पर हो सकती थी इसलिए यूरिया के 10 प्रतिशत दाम बढाने से हमको 710 करोड़ के लगभग बचत होगी, 10 प्रतिशत से। उसमें हमने एक अप्रैल से, सब्सिडी डी.ए.पी. पर जो 3000 रुपये प्रतिटन थी, उसके स्थान पर 3725 आयातित डी.ए.पी. पर 1500 थी, उसके स्थान पर 2250 पोटाश पर 1500 की जगह दो हजार और एस.एस.पी. पर 500 की जगह 600 एक अप्रैल से कर दिया है ताकि उसका पूर्ण लाभ हमारे किसानों को मिले।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : मैडम मेरे दूसरे पार्ट का जवाब मंत्री ने दिया था कि जो स्टाक था, उस स्टाक का क्या बनेगा?

श्री शीश राम ओला : स्टाक के लिए ....

उपसभापति : मंत्री जी हो गया। क्वेश्यन न. 103।

Rise In the Prices of Major Agricultural Inputs

*103. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased lo state:

(a) the percentage of rise ir: the prices of major agricultural inputs during the years 1995-96 and 1996-97;

(b) the percentage of rise in the support price of major foodgrains during this period; and

(c) the percentage of rise in the production of these foodgrains during this period?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) A tatement is laid on the table of the house.

Statement

(a) to (c) Statement showing the annual percentage variations in the prices of major agricultural inputs as measured ny the wholesale price index numbers, the minimum support prices of foodgrains and the production of foodgrains during the years 1995-96 and 1996-97 are given at statement I, II and III respectively.

Statement-l

Percentage annual variation in the prices of major agricultural inputs during 1995-% and 1996-97 as measured by the wholesale Price Index Numbers (Base 1981-82=100)

Commodities	Weight (%)	1995-96	1996-97 (as on 8.2.1997)
Fertilizers	1.748	5.1	-0.8
Pesticides	0.202	-15.4	0.5
High Speed Diesel	2.164	0.0	14.8
Lubricants	0.453	9.6	3.6
Light Diesel Oil	0.203	-0.1	29.6
Electricity for Irrigation	0.317	0.0	13.8
Tractors	0.348	5.9	8.5
Power Driven Pumps	0.208	7.2	16.3
A verve	5.638	2 4	8.7

Statement-II

Percentage rise in the Support Prices of Major Foodgrains

Crop	Weight in Index of Agril. Production (%)	1995-%	1996-97
Paddy	29.74	5.9	5.6
Jowar	4.43	7.1	3.3
Bajra	1.87	7.1	3.3
Maize	2.41	6.9	3.2
Ragi	0.95	7.1	3.3
Wheat	14.45	5.6	9.2
Barley	0.66	3.5	3.4
Tur (Arhar)	1.58	5.3	5.0
Moong	*	5.3	5.0
Urad	*	5.3	5.0
Gram	3.07	4.5	5.7
Average	59.16	5.9	6.1

*Moong and Urad have not been assigned separate weights in the agricultural Production Index.

Statcment-III

Percentage variation in the Production of Foodgrains

Crop	1995-96	1996-97*
Rice	-2.68	+0.01
Wheal	-4.79	+3.00
Jowar	+6.47	+ 14.97
Bajra	-24.72	+38.59
Maize	+6.30	+2.22
Ragi	+ 17.95	-5.08
Barley	-4.62	-9.09
Cereals	-3.16	+3.11
Tur	+ 10.28	+25.85
Gram	-22.04	+9.56
Pulses	-6.05	+6.14
Foodgrains	-3.37	+3.27

'Since the figures relating to foodgrain production for 1996-97 are not final as rabi and summer crops are yet to be harvested, the percentage variations for 1996-97 are based on ' estimated production.

श्री इकबाल सिंह : महोदया, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, कंपेरिजन में ऐग्रीकल्चर इन्पुटस के रेट 1995-96 और 1996-97 में बहुत बढे है। महोदया, अभी मेरे माननीय मित्र श्री सुरजेवाला जी भी यूरिया के बारे में बात करे रहे थे कि 10 परसेट उन्होंने अभी-अभी रेट बढाए है। महोदया, अभी उन्होंने वीट के भी रेट फिक्स किये थे और 415 रुपये पर क्विंटल रेट फिक्स किया था। रेट फिक्स करने के बाद फिर उन्होंने यूरिया का रेट 10 परसेंट बढाया तो इस तरह से ऐग्रीकल्चर इनपुटस जो मंत्री जी ने बताया है, जैसे बीज है, दवाइयां है, बिजली है, ट्रैक्टर है, इन सबके रेट इन सालों में बहुत बढे है। मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी यह बताएं कि क्या इन बढे हुए रेटो का हमारे किसान मुकाबला कर सकेंगे? हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग किसानो के रुप में काम कर रहे है लेकिन 70 प्रतिशत लोग इसका मुकाबला नही कर पाएंगे क्योकि ऐग्रीकल्चर इनपुटस मंहगे हो रहे है और उन्होंने उसके मुकबाले बहुत कम रेट फिक्स किये है। तो मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान के लिए क्या आपने कुछ सोचा है? अभी आप पंजाब में देखिए कि 65 प्रतिशत फूड सैट्रल पूल में दे रहे है तो पंजाब का किसान और भार का किसान, सारे किसान इन बढे हुए मूल्यों का मुकाबला नही कर पाएंगे। तो क्या मंत्री जी कोई ऐसा प्रभावी या ठोस कदम उठाएंगे जिससे भारतीय किसान अच्छी तरह से गुजारा कर पाएं?

श्री एस. एस. सुरजेवाला : गेहूं का रेट पांच सौ रुपये से कम नही होना चाहिए।

उपसभापति : मंत्री जी को बोलने दीजिए। आप मंत्री बनेंगे तो आप जवाब दीजिएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम, यह सच है कि जो इनपुटस का दाम बढा है, वह ज्यादा और है और जो सप्रोर्ट प्राइस हमने दिया है वह 6 परसेट बढ़ा है ऐवरेज इनपुटस का दाम 8 परसेट बढा है। यह आपका कहना सही है लेकिन एक ही फैक्टर्स होते है। इसके बावजूद भी मै समझता हूं कि किसानों को इसमें घाटा हो रहा है। इसलिए मै इस बात को समझने हुए आपसे कहना चाहूंगा कि कास्ट आफ प्राडक्शन में हायर लेबल, मेटेनेस एक्सपौसिस, आन एनीमले एक्सपौलाइजर्स मोनियोर्ज, पेस्टी साइडस एंड इरीगेशन एक्सेक्ट्रा, डेप्रिशएशन आन इम्पलीमेटस एण्ड फार्म बिल्डिगस, लेंड रेवेन्यू रेंट पेड़ फार रीजेंसी, इम्प्यूटिड अमाउन्ट आफ फैमली लेबर एण्ड

मनाजयरिल कास्ट ये सभी इनकलूड करते है। इसके अलावा डिमाण्ड एंड सप्लाई पोजीशन को देखना पड़ता है और जो आपने कहा कि गरीब किसान भी तो बहुत है जिनको खरीदना पड़ता है । इन सारी बातों को देखते हुए ही सीएसीपी मूल्य निर्धारित करती है। उसके मुताबिक ही हमने अभी इनको इतना बढ़ाया है। आगे क्या कर सकेंगे वह सब देख लेते है। अगर आप ज्यादा अत्र संग्रह कर देंगे प्रोक्योरमेंट में तो फिर हम उसके बाद सोचेगे कि आपको कुछ इनाम भी दिया जाये। अगर कोटा पूरा हो जाएगा तो आप इनाम ले लीजिएगा हमसे।

श्री इकबाल सिंह: मैडम, अभी मंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से उत्तर दिया और किसानों के घाटे को बता दिया कि किसानों को घाटा होता है। क्या मंत्री जी आप भारतीय किसानों को जो कि गेहूं, चावल बोते हैं उनकी खरीद पर आप कोई बोनस देने के लिए तैयार है, जबकि उनको घाटा हो रहा है? मंत्री जी जैसा कि आप जानते है कि कोई बार मौसम की बजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है तो क्या आपने उनकी फसल के इंश्योरेंश के लिए कोई आर्डर दिया है? क्या इंडस्ट्री सैक्टर की तरह भारतीय किसानों को सभी बैंकों से कोई मदद देने के लिए आपने कहा है? इसलिए माननीय मंत्री जी से मै यह जानना चाहता हूं कि आप नये इन-पुट्स उनके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे है तो आप किसानों की किस ढंग से मदद करेंगे? और जो अभी आपने किसानों के घाटे के बारे में बताया तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र: मैडम, इनके प्रश्र के तीन अंश हैं। पहला अंश कुछ बोनस देने के बारे में है तो अभी तो यह स्टेज आई नहीं है। मैंने तो आपसे कहा ...(**व्यवधान**)... हम ने यह कहा कि अगर जो कोटा प्रोक्योरमेंट का है वह पूरा होगा तो हम उस पर सोचेंगे।

श्री इकबाल सिंह: आपके किसान और पंजाब के किसान ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: इकबाल जी पहले वह जवाब तो दे दें। उसके बाद किसानों के दर्द की बात कहिएगा।

श्री चतुरानन मिश्र: एक हिस्सा तो यह हुआ। दूसरा हिस्सा यह था कि उनके लिए फसल बीमा टाइप की कोई चीज की जाए, उनके लिए एश्योर्ड किया जाए। असल में पंजाब नहीं चाहता कि एश्योर्ड हो, जबकि सारा भारत चाहता है। पंजाब को एश्बोर्ड इरीगेशन है, इसलिए आपकी सरकार नहीं मानती है, हम क्या करे? अगर पंजाब शरीक हो जाए तो हमको बड़ी प्रसन्न्ता होगी कि वह उसमें आ जाये, तो हम उसके लिए भी करेंगे। जहां तक कर्ज देने को व्यवस्था है और भी मदद उनको क्रेडिट में मिले तो उसके लिए कुछ घंटे इन्तजार कीजिए, सात बजे तक आपको कुछ मालूम हो सकता है। अगर नहीं हो तो फिर आप हमसे कहिएगा।

उपसभापति: आपका सप्लीमेंट्री हो गया। मंत्री जी ने बजट के बारे में कह दिया।

SHRl V. NARAYANASAMY: Miidam, the hon. Agriculture Minister just gave a rosy picture about (he agricultural community as a whole. He further said that they would get something more in the evening. *(Interruptions)*

SHRl CHATURANAN MISHRA: What I have said was that after seven o'clock today, if you are not satisfied, then you put this question the next day. I have not given any assurance. *(Interruptions)*

SHRI SATISH AGARWAL: That is a sufficient indication for any intelligent person. *(Interruptions)*

SHRl CHATURANAN MISHRA: It seems that the hon. Member is intelligent. But he should be intelligent enough not to take it as an assurance.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I went through the figures that the hon. Minister has given about the percentage variations in the production of foodgrains and also the support price which the Government is giving. Madam, the average of support price, as given by the hon. Minister, is 6.1 per cent and the increase in the variation of prices or in the cost of agricultural inputs is +3.27 per cent. That is what the hon. Minister has said. Madam, I dispute these figures because these are the figures which have been collected from various sources and the Govemment has arrived at these Figures. Madam, the point is that agricultural workers want double the salary. Rs. 17 is per day salary of an agricultural worker.. The Minister has given the figures relating to tractors? How many farmers in the country are having tractors? Not even seven or eight per cent. Today, the fertiliser prices have also increased. They have increased by

ten per cent, that has not been given here. Let the hon. Minister come with a realistic figure. Now she farmers are selling their land and are migrating to the cities because they are losing in agriculture. The Government is not giving adequate support price to the farmers. Let the Minister be realistic and give us an assurance in the House that he will arrive at a realistic figure and try to support the farmers according to the cost input. Let him say that.

श्री चतुरानन मिश्र: मैडम, हमने किसानों को गेहूं की कीमत 35 रुपये दी है। इससे पहले उनको गेहूं की कीमत इतनी कभी नहीं मिली इसके बावजूद भी आप लोग कहते है। हमने किसानों को अब तक सबसे ज्यादा कीमत दी है। लेकिन प्राइस का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं सदन को कहना चाहता हूं कि मेरी चिन्ता इस बात पर है कि आप लोग भी मदद कीजिये। प्राइस सिर्फ इस पर ही निर्भर नहीं करता है कि सिर्फ किसानों को ही मिले। देश का एक बड़ा हिस्सा भी है, मार्जिनल फार्मर्स भी जिसमें शामिल है और स्माल फार्मर्स भी है जिनको अत्र खरीदना पड़ता है हम्को उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे करे? देश में जिस तरह से लिबरलाइजेशन की इकनोमी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा।

इस बात से हम सब चिंतित है। वर्तमान सरकार एक नया रास्ता चुनना चाहती है। मैं माननीय सदस्यों के सामने अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। आपसे मैं ग्रहण करुंगा अभी या बाद में। हम लोग चाहते है कि बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हम सस्ते दामों मे दें। पहले हम इनको प्रोटेक्ट करें ताकि इनके जीवनयापन पर खतरा न हो तब फिर हम प्राइस राइस की ओर देखेंगे अगर कहें कि उधर प्राइज बढ़ा दिया जाये, तो यों ही वे गरीब लोग आलोचना करते है कि आपने तो 35 रुपये बढा दिये, इसका यह असर हुआ कि गेहूं का दाम बढ़ गया, एक आलोचना हमको यह भी सुननी पड़ती है। इसलिए हम चाह रहे है कि उसमें हमने एक छोटा सा कदम उठाया है उनको आधी कीमत पर देने का और दूसरा भी उठ सकता है अगर माननीय सदस्य और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग सहयोग करें। जरुरत है एकुयल में कौन बोको पाक्टी लाइन के है वह जानना बड़ा कठिन है। अगर वह छोड़ दिया जाता है एक ब्लाक, दूसरे लेवल पर तो उन्की संख्या इतनी ज्यादा हो गी जो भारत की पापुलेशन से भी बहुत ज्यादा बढ जायेगी। इसलिए आपके सहयोग की जरुरत है। यह नया प्रयास है, हमको वल्ड से कम्पलीट करना पड़ेगा। इसलिए हमको अपने किसानों को ज्यादा दाम देना होगा, लेकिन ज्यादा दाम के चलते गरीब लोग तबाह हो जायेंगे, यह कभी बर्दाशत नही किया जायेगा। यह गणतंत्र के हित में नही होगा, डेमोकेसी के हित में नही होगा। इसलिए हम प्रोटेक्ट करना चाहते है। यदि यह प्रयस सफल रहा अगर बिलो पावर्टी लाइन की संख्या उचित संख्या हो सकी अगर डिस्ट्रिबयूशन सिस्टां सही हुआ तो हम आपको विश्राम दिलाते है कि दूसरे काम भी जैसे इरिगेशन, बिजली और पानी इत्यादि उसी आधार पर करेंगे। हम लोगों को और भी सुविधाएं देने का काम करेंगे। लेकिन दि नम्बर आफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन, वो स्टेब्लिश हो जायेगा। हम सहयोग चाहते है कम से कम कांग्रेस पार्टी का।

श्री जानर्दन यादव : वह सही नही होगा।

श्री चतुरानन मिश्र : हो सकता है गलती हो, हम आपसे तो कह रहे है कि हम नया प्रयास कर रहे है लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बिलो पावर्टी लाइन के लिए बोलती रही है उससे तो जरुर अपील करेंगे कि इसमें सहयोग। दीजिए ताकि हम लोग डिटरमाइन करें। यादव जी, मै आपको भी जितना जानता हूं आपसे भी आग्रह करेंगे कि गरीबों के लिए अगर हम डिटरमाइन कर लें तो हमारा देश ....

SHRI V. NARYANASAMY: We support the farmers. We also support you on that

SHRl CHATURANAN MISHRA: I have told you just now that first I would protect the vulnerable sections of society and then I will try to give equal benefits as desired by our learned friend who has just spoken. I am evolving such a policy. But it will take time. As regards the point that the actual subsidy should reach the farmers, I shall be the happiest man, if any such scheme is evolved. It is very difficult to send the subsidy individually to millions of farmers. I want to have something like the Khadi Commission. It should be there. But it is becoming difficult. Khadi has got a small number of people. Moreover, khadi has got a surplus economy. But this has got a deficit economy. That is why that principle is not working. Anyhow, I would request you to suggest to me any

other mechanism. 1 will co-operate with you fully.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister Sahib has given the entire policy for the future also. So, wc can go to Question No. 104. ***(Interruptions***)….आई नो इस पर किंसी और समय पर डिसकस करेगे । दो क्वेक्षन मे ही क्वेक्षन आवर खत्म हो रहा है । जिचकर जी आपने तो क्वेक्षन पूछ लिया?

Apprehension regarding rise in the prices of Urea

*104. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA J1CHKAR:

Wil! the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is an apprehension amongst tanners that the prices of urea will be raised;

(b) if so, Government's proposal to eliminate this apprehension from the minds of farmes and

(c) the steps being taken to keep the prices of urea down?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The price of urea has been increased by 10% with effect from 21.2.1997 for the present in order to reduce the imbalance in the application of NPK nutrients.

(c) The price of urea is already much lower compared to the decontrolled fertilizers. However, since the country's requirement of Urea is met through both indigenous production and imports, which is much costlier, any reduction in price of Urea is possible only if imports are avoided.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, a high-power committee headed by the noted economist, Shri Hanumantha Rao, was appointed to go into the entire gamut of the retention price mechanism of urea. When this question of hiking the price of urea by 10% had gone before the Cabinet Committee on Economic Affairs, a decision was deferred. An official spokesman of the Ministry said that there would be no hike in the price of urea until the Hanumantha Rao Committee gave its report. This was said on the 17th of February, 1997. On 17th February, an official spokesman of the other Ministry, that is, Mr. Ola's Ministry, said that there would be no increase in the price of urea and that the Cabinet had deferred a decision. On 21st February, they made an announcement that there would be an increase of 10% in the price of urea. Now what has happened in these four or five days necessitating this drastic decision?

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम, माननीय सदस्या को कैबिनेट की जितनी जानकारी है उतनी शायद हम को नही है और हमारी लाचरी है कि हम रख भी नही सकते है। इसलिए इस पर मै कुछ नही कहूंगा। लेकिन मै एक बात कहना चाहता हूं कि हनुमंतराव कमेटी जो बनी है उसका दूसरा काम है। इसको भी देखेगी लेकिन उसका दूसरा काम है। मै बहुत ध्यान से सुन रहा था जब माननीय सदस्य-गण पूछ रहे थे कि प्राइवेट कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा और वह ज्यादा लाभ उठा रहे है। मै इसको सुन रहा था। लेकिन हमको अधिकार नही था। अब अधिकार है और हम आपको कहना चाहते है। यह ठीक है कि जो कैपिटल रिलेटेड एक्स्पेडीचर होता है उसकी 100 परसेट कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें एक कंपनी ऐसी है, उसने अपनी कैपेसिटी 143 परसेंट दिखाई है और उस पर वह प्राइस लेता चला जा रहा है।

उपसभापति : **नाम लेने में कोई हर्ज नही है। वह पुरुष या महिला नही है।**

A company's name can be mentioned. You should not mention the names of those people who cannot defend themselves here.

श्री चतुरानन मिश्र : पुरुष और महिला वे तो सिर्फ हिन्दी में लागू होते है। संस्कृत में तीन जैडर होते है।

उपसभापति : तीसरे जैडर का नाम लेना अलाउड है।